भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1662
10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र से जुड़ा प्रशिक्षण

1662. **मोहम्मद रकीबुल हुसैनः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने असम में युवाओं हेतु औद्योगिक कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) भारी उद्योग क्षेत्र से जुड़े केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है;
(ग) क्या कोई उद्योग-कौशल लिंकेज केंद्र स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार ने ऐसी प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क), (ग) और (घ): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) से प्राप्त सूचनानुसार, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) पूरे देश में, जिसमें असम भी शामिल है, युवाओं को कुशल बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के देशव्यापी नेटवर्क के ज़रिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीस) कार्यान्वित कर रहा है। प्रशिक्षण महानिदेशालय प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रशिक्षण का वातावरण उपलब्ध कराने, उद्योग के साथ जुड़ाव को मज़बूत करने और उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी और उद्योग के तरीकों से परिचित कराने के लिए फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन स्कीम और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) भी कार्यान्वित कर रहा है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) 'भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम-II' (पूंजीगत वस्तु स्कीम) लागू कर रहा है, जो पूरे भारत में मांग आधारित स्कीम है। भारी उद्योग मंत्रालय ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को मंज़ूरी प्रदान की है:

i. ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी), नई दिल्ली द्वारा 23 अर्हता पैक का विकास;

ii. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए पूंजीगत वस्तु कौशल परिषद, नई दिल्ली द्वारा 23 अर्हता पैक का विकास;

iii. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन (आईएएससी) सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा 12 अर्हता पैक का विकास।

इन कौशल परिषदों को कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैकेज (क्यूपी) विकसित करने का काम सौंपा गया है, जिससे मानकीकृत, उद्योग से संबंधित कौशल क्षमताएं सृजित हो सकें, जिनका उपयोग कार्यबल के कौशल स्तरोन्वयन के लिए किया जा सके, जिससे पूरे भारत में, जिसमें असम भी शामिल है, स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा मिल सके।

(ख): जहां तक भारी उद्योग मंत्रालय का प्रश्न है, ऐसा कोई डेटा नहीं रखा जाता है।

*****